International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 9, Issue 06, June 2022
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

# भारत में शिक्षा और आर्थिक विकास

**Mrs. Rashmi Kumari**
Reserach Scholar
Nirwan University, Jaipur

**–: सार :–**

यह संक्षिप्त सर्वेक्षण भारत में शिक्षा के प्रतिफल की जांच करता है, और फिर भारत के विशेष संदर्भ में आर्थिक विकास और आर्थिक विकास दोनों पर शिक्षा की भूमिका की जांच करता है। इसका उद्देश्य शिक्षा नीति के लिए अनुभवजन्य परिणामों के निहितार्थ निकालना है। परिणाम बताते हैं कि भारत में महिला शिक्षा का विशेष महत्व है। वे यह भी सुझाव देते हैं कि संभवत इसके द्वारा उत्पन्न बाहरीताओं के कारण, प्राथमिक शिक्षा अपेक्षाकृत कम निजी प्रतिलाभ दर से प्राप्त होने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है।

**भारत में शिक्षा और आर्थिक विकास**

एक आर्थिक वस्तु के रूप में शिक्षा के विश्लेषण का एक लंबा इतिहास रहा है। बेकर (1962) और शुल्त्स (1962) के मौलिक कार्य ने शिक्षा का एक औपचारिक मॉडल एक निवेश वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने मानव पूंजी के भंडार को बढ़ाया। व्यक्तियों ने किसी भी अन्य निवेश निर्णय के रूप में उसी तरह से शैक्षिक विकल्प बनाए, जिनमें सभी की सामान्य विशेषता है कि अब भुगतान की गई निवेश लागत समय के माध्यम से लाभ का प्रवाह उत्पन्न करती है जिसका वर्तमान छूट मूल्य वर्तमान लागत के साथ तुलना करना है। इसके बाद, शिक्षा में वापसी की दर को मापने का प्रयास करने वाले अर्थमितीय अध्ययनों का एक बड़ा हिस्सा था – तथाकथित मिनसेरियन दृष्टिकोण – जबकि अन्य चरों के ढेरों को नियंत्रित करने के लिए उचित रूप से कमाई को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है। प्रशिक्षण परिणामों, शैक्षिक सब्सिडी और शुल्क का अध्ययन करने के लिए इस बुनियादी मानव पूंजी मॉडल के विस्तार का हाल ही में लाभ उठाया गया है।

विकास और विकास अर्थशास्त्र के भीतर, आर्थिक चर के रूप में शिक्षा के महत्व का भी एक विशिष्ट इतिहास है, जिसकी शुरूआत लुईस (1962) से हुई है। कौशल के उचित मिश्रण के बारे में प्रश्न, किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, शिक्षा के बीच संबंध और शिक्षित श्रमिकों को उत्पादक रोजगार में अवशोषित करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का अध्ययन औपचारिक मॉडल की सीमाओं के बाहर किया गया है।

हाल ही में, अंतर्जात विकास में रूचि के पुनरूत्थान – तथाकथित न्यू ग्रोथ थ्योरी (बैरो (1991), बैरो और साला-ए-मार्टिन (1995), लुकास (1998) ने आर्थिक विकास में शिक्षा की संभावित भूमिका के औपचारिक विश्लेषण को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया है। हालांकि इस बात पर जोर

© Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

दिया जाना चाहिए कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक ही चीज नहीं हैं। आर्थिक विकास एक घटक है, हालांकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण अंतर को सृजन द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। आर्थिक विकास में गैर-जीडीपी योगदान पर चर्चा करते समय इस सूचकांक ने उद्योग मानक का दर्जा हासिल कर लिया है।

भारत में, शायद कई विकासशील देशों की तुलना में, गैर-जीडीपी आयाम का बहुत अधिक महत्व है। व्यापक पैमाने और विविधता का अर्थ है कि विकास प्रक्रिया को बहुआयामी पैमाने पर असमानता और बहिष्करण के मुद्दों से निपटने के लिए बल मिला है। अधिकांश विकासशील देशों को अपने विकास एजेंडा के हिस्से के रूप में गरीबी, लिंग भेदभाव, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता, बाल श्रम, आय असमानता आदि में कमी पर जोर देना पड़ा है। भारत में ऐसे अतिरिक्त कारक हैं जो विकास प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और उसे काटते हैं- जाति और अस्पृश्यता, धर्म, भाषा, सबसे महत्वपूर्ण नाम हैं।

**भारत में शिक्षा पर वापसी की दरें**

दत्ता द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन (2006) में भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग करते हुए पाया गया कि वयस्क पुरूषों के लिए शिक्षा की दरों का पैटर्न अन्य जगहों से भिन्न नहीं है। आकस्मिक श्रमिकों और नियमित श्रमिकों के लिए रिटर्न काफी भिन्न थे। उत्तरार्द्ध में शिक्षा के स्तर के संबंध में सामान्य रूप से उल्टा 'यू' आकार का वक्र था, जबकि आकस्मिक श्रमिकों के लिए रिटर्न सपाट था। इस बात के भी कुछ प्रमाण थे कि 1990 के दशक की अवधि में नियमित श्रमिकों के लिए स्नातक प्राथमिक शिक्षा से दूर हो रहे थे। लेखक सुझाव देते हैं कि यह व्यापार उदारीकरण के कारण हो सकता है।

हालांकि इस तरह के अध्ययन सार्थक हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए कि संपूर्ण मानव पूंजी दृष्टिकोण शिक्षा के वित्तपोषण के लिए क्रेडिट बाजारों तक प्रतिस्पर्धी पहुंच पर आधारित है। यदि शिक्षा को राशन दिया जाता है ताकि कम आय वाले परिवारों के लोगों को शिक्षा प्रक्रिया से बाहर रखा जा सके, तो वापसी की दर के अनुमानों को सशर्त के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण पेपर तिलक (2002) में ग्रामीण भारत में मानव विकास पर उपयोगकर्ता एनसीएईआर डेटा यह प्रदर्शित करने के लिए कि प्राथमिक शिक्षा पर घरेलू खर्च कम से कम उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा तक पहुंच के लिए वित्तीय बाधाओं के पुख्ता सबूत नहीं हैं। कम से कम प्राथमिक स्तर पर, यह प्राथमिक शिक्षा में वापसी की दरों को एक अच्छा पहला सन्निकटन होने का समर्थन देता है।

माध्यमिक शिक्षा (12 से 24:) की तुलना में प्राथमिक शिक्षा में रिटर्न कम (2 से 10) पाया गया। आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रतिफल कम विकसित राज्यों में सबसे अधिक थे जहां गरीबी अधिक स्पष्ट है। एक समानांतर अध्ययन में दुरईसामी (2002) ने पाया कि महिलाओं की वापसी महिलाओं की तुलना में अधिक है। हालांकि, किंगडन और उन्नी (2001) बताते हैं कि महिलाओं की शिक्षा में वापसी की उच्च दर को इस तथ्य के खिलाफ स्थापित किया जाना चाहिए कि भेदभावपूर्ण अंतर-पारिवारिक व्यवहार के कारण महिलाओं की शिक्षा का स्तर निम्न है। वे दिखाते हैं कि महिलाओं की स्कूली शिक्षा के निचले वर्षों में वापसी की उच्च दरों से सकारात्मक प्रभाव प्रभावी रूप से रद्द कर दिया गया है, अन्य बलों को महिलाओं के लिए कम मजदूरी के लिए लेखांकन में व्याख्यात्मक भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिया गया है।

विकास में शिक्षा की भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू 'अति-शिक्षा' की स्पष्ट संभावना है। ऊपर उद्धृत अध्ययनों से पता चलता है कि माध्यमिक शिक्षा से परे वापसी की दर बहुत अधिक नहीं है। फिर माध्यमिक शिक्षा के बाद के क्षेत्र में विस्फोट क्यों हो रहा है? आकस्मिक अवलोकन से स्नातक

बेरोजगारी और अल्प-रोजगार के बहुत उच्च स्तर का पता चलता है। यह विचार शर्मा एट अल (2002) द्वारा समर्थित है, जो हाल के वर्षों में ंविशेष रूप से शिक्षित श्रमिकों के लिए नौकरी के बाजार के सिकुड़ते रिश्तेदारू पर ध्यान देते हैं। यह स्नातकों के बीच ब्रच्छन्न बेरोजगारीः की काफी मात्रा का सुझाव देता है जो खुद को नौकरी करने वाले स्नातकों के रूप में प्रकट करता है जिसके लिए वे अयोग्य हैं। एक बार फिर यह शिक्षा में वापसी की दरों को पूर्वाग्रहित कर सकता है जैसा कि यूके के संदर्भ में चटर्जी एट अल (2003) द्वारा दिखाया गया है।

नीति के दृष्टिकोण से, वापसी अध्ययन की ये दर कुछ उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। परिणाम शिक्षा नीति विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं जो विकास के वर्तमान स्तरों पर आकस्मिक हैं। एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। वे भी सुझाव देते हैं कि नीति पर विचार करने से पहले, शिक्षा और श्रम बाजार के बीच अंतः क्रिया का ठीक से लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता है।

**आर्थिक विकास और शिक्षा**

लुकास (1988) का सेमिनल पेपर न केवल शिक्षा और विकास के बीच संबंधों को समझने के लिए केंद्रित था, बल्कि यह भी था कि शैक्षिक पहल को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के लिए एक मजबूत मामला क्यों हो सकता है। एक ब्जए विकासः मॉडल के संदर्भ में, लुकास ने सुझाव दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की उत्पादकता तब अधिक होती है जब अन्य उच्च उत्पादकता वाले श्रमिकों द्वारा एक तरह के सीखने के तंत्र के माध्यम से काम करने वाले वातावरण में काम करते हैं। यह इस प्रकार है कि एक क्षेत्र जिस विकास पथ को अपनाता है वह विकास प्रक्रिया की शुरूआत में संचित मानव पूंजी के स्तर पर निर्भर करता है। लुकास मॉडल का उपयोग शिक्षा से उत्पन्न होने वाली निहित सकारात्मक बाहरीता के कारण शैक्षिक सब्सिडी को सही ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। क्रॉस कंट्री अनुभवजन्य अध्ययनों में विशेष रूप से बैरो (1991) ने पाया कि एक बार अन्य कारकों को नियंत्रित करने के बाद, मानव पूंजी का वास्तव में विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बैरो का विश्लेषण प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा - काफी बुनियादी शिक्षा चर के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पर केंद्रित था। इसी तरह की पद्धति का उपयोग करते हुए, चटर्जी (1998) ने इसे तृतीयक शिक्षा को शामिल करने के लिए बढ़ाया और एक समान सकारात्मक परिणाम पाया।

1966 से 1996 तक भारतीय डेटा का उपयोग करते हुए, सेल्फ एंड ग्रैबोव्स्की (2004) ने भारतीय विकास प्रदर्शन पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा के कारण प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समय श्रृंखला तकनीकों का इस्तेमाल किया। परिणामों ने माध्यमिक शिक्षा के लिए कमजोर साक्ष्य के साथ प्राथमिक शिक्षा के महत्व की पुष्टि की और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तृतीयक शिक्षा का विकास पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। तृतीयक शिक्षा की स्पष्ट अप्रासंगिकता निश्चित रूप से है

पूरी तरह से ऊपर उल्लिखित स्नातक प्रच्छन्न बेरोजगारी परिकल्पना के अनुरूप है। लेकिन शायद स्वयं और ग्रैबोव्स्की की सबसे दिलचस्प खोज विकास प्रक्रिया में महिला शिक्षा (सभी स्तरों पर) का महत्व है। यह दुरईसामी (2002) के परिणामों का समर्थन करता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा में वापसी की दर अधिक थी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यापार उदारीकरण सुधार शुरू होने से पहले अध्ययन की अवधि समाप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, डेटा एक बंद अर्थव्यवस्था से आता है। विश्व बैंक में भल्ला के काम पर भरोसा करते हुए जैन (2004) द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण लाभ केवल एक खुली अर्थव्यवस्था में है जो अतिरिक्त ज्ञान का पूरी तरह से लाभ उठाने में सक्षम है। यह अस्थायी रूप से सुझाव दिया गया है कि खुले युग में, यदि भारत स्कूली शिक्षा के औसत स्तर को दो

साल तक बढ़ा सकता है, तो इससे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.15–0.2 प्रतिशत की स्थायी वृद्धि होगी।

एक अन्य उदारीकरण पूर्व अध्ययन में, अंसारी और सिंह (1997) ने शिक्षा और विकास पर सार्वजनिक खर्च के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए 1951 से 1987 तक वार्षिक समय श्रृंखला का उपयोग किया। वे दोनों के बीच कोई दीर्घकालिक संबंध नहीं पाते हैं, जो ब्बंद अर्थव्यवस्था नए ज्ञान का लाभ उठाने में विफल॰ परिकल्पना के अनुरूप है। हालांकि, वे शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च से लेकर निजी पूंजी निर्माण और इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से विकास पर प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध पाते हैं। इसी तरह, 1970–94 से भारतीय राज्यों के एक अध्ययन में, नागराज एट अल (2000) अंतरराज्यीय असमानता को बनाए रखने में राज्यों में विकास और शैक्षिक असमानताओं में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका के मजबूत सबूत पाते हैं।

**आर्थिक विकास और शिक्षा**

भारतीय संदर्भ में, आर्थिक विकास को आर्थिक विकास के पर्याय के रूप में नहीं देखा जा सकता है। आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाएगा। यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। एक बार जब कोई आर्थिक विकास के व्यापक दृष्टिकोण पर विचार करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा और शिक्षा नीति की भूमिका (संभावित रूप से कम से कम) और भी बड़ी हो जाती है।

भारत में आर्थिक विकास की छत्रछाया में यथोचित रूप से शामिल मुद्दों के समूह में सभी प्रकार की असमानता और बहिष्करण (चाहे आय, लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर), स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता और शिशु मृत्यु दर और बाल श्रम शामिल हो सकते हैं। व्यापक शब्दों में, अर्थशास्त्रियों के अनुभवजन्य शोध से पता चलता है कि भारत में, इन मुद्दों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक महिलाओं की शिक्षा है। उदाहरण के लिए, ड्रेज और मूर्ति (2001) बताते हैं कि कम प्रजनन क्षमता का निर्धारण करने वाला एक प्रमुख कारक उच्च महिला शिक्षा है, जबकि शहरीकरण, गरीबी में कमी और पुरूष साक्षरता जैसे आधुनिकीकरण के सामान्य संकेतकों का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। जाति के मुद्दों के संबंध में तस्वीर कम आशाजनक है। ब्पिछड़ी जातियों॰ की शिक्षा में काफी सरकारी निवेश के बावजूद, इन जातियों को आर्थिक लाभ के बहुत कम सबूत हैं, आंशिक रूप से बेहतर नौकरियों को देने के लिए शिक्षा की अक्षमता के कारण। यह स्वाभाविक रूप से एक ब्हतोत्साहित कार्यकर्ता॰ प्रभाव और ऐसी जातियों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए धन की निकासी की ओर जाता है। एक महत्वपूर्ण अध्ययन में, जेफरी एट अल (2004) ने निष्कर्ष निकाला है कि ब्समाज के भीतर भौतिक संपत्ति में पर्याप्त पुनर्वितरण के बिना, औपचारिक शिक्षा पर केंद्रित विकास पहल केवल अधीनस्थ समूहों की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में आंशिक रूप से सफल होने की संभावना है॰।

**निष्कर्ष**

अनुभवजन्य साहित्य की आम सहमति यह प्रतीत होती है कि वापसी की दरें वास्तव में (उल्टे) यू आकार की हैं जो माध्यमिक शिक्षा के लिए सबसे बड़ी हैं। हालांकि, वापसी की सभी दरें

शिक्षा उन क्षेत्रों में अधिक है जहां विकास कम है। एक स्पष्ट रूप से विरोधाभासी निष्कर्ष यह है कि प्राथमिक शिक्षा में वापसी की दर काफी कम है, लेकिन फिर भी विकास के प्रतिगमन में, यह प्राथमिक शिक्षा चर है जिसका सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है। यह इस संभावना का सूचक है कि प्राथमिक शिक्षा में लुकास प्रकार की बाह्यता है। प्रतिफल की मापी गई निजी दरें प्रतिफल की सामाजिक दर से कम हैं। यदि यह अनुमान सही है – और यह अंतर–राज्यीय डेटा का उपयोग करके परीक्षण योग्य है – तो इसका सार्वजनिक नीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि

**महिलाओं के लिए कोई समान प्रभाव नहीं है जहां उच्च निजी प्रतिलाभ दर पहले से ही महिलाओं को शिक्षित करने से उच्च विकास दर में दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा के आगे विस्तार के जोखिमों को भी प्रलेखित किया गया है। इसी तरह, श्रम बाजार नीति में प्रतिपूरक परिवर्तनों के बिना षपिछड़ी जातियोंष को शिक्षित करने में निवेश करने की नीति संभावित रूप से प्रतिकूल साबित हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि महिलाओं के लिए एक संकीर्ण आय के दृष्टिकोण से, महिलाओं के लिए निजी और सामाजिक आर्थिक रिटर्न के बीच कोई अंतर नहीं प्रतीत होता है, महिला शिक्षा को बढ़ाने से विकासात्मक रिटर्न बड़ा प्रतीत होता है।**

**References**


Ansari,M.I., and Singh,S.K.,(1997) "Public Spending on education and Economic Growth in India:Evidence from VAR Modelling" *Indian Journal of Applied Economics*, 6(2),pp. 43-64.

Barro,R.J.,(1991) "Economic Growth in a Cross section of Countries", *Quarterly Journal of Economics,* 106(2), pp. 407-443.

Barro R.J.,and Sala-i-Martin,X (1995) "Economic Growth", *McGraw Hill*.

Becker.G, (1962) "Investment in Human Capital", *Journal of Political Economy,* 70,S9-S49

Chatterji,M., (1998) "Tertiary Education and Economic Growth", *Regional Studies,* 32(4), pp.349-354.

Chatterji,M., Seaman,P.T., and Singell,L., (2003) "A test of the signalling hypothesis", *Oxford Economic Papers,* 55(2), pp. 191-215.

Dreze,J., and Murthi,M.,(2001) " Fertility, Education and Development: Evidence From India", *Population and Development Review,* 27(1), pp33-63

Duraisamy,P.,( 2002) "Changes in Returns to Education in India,1983-94: By Gender, Age-Cohort, and Location", *Economics of Education Review*, 21(6), pp 609-622.

Duraisamy,P., and Duraisamy,M.,(2005) "Regional Differences in Wage Premia and Returns to Education by Gender in India", *Indian Journal of Labour Economics,* 48(2), pp335-347.

Dutta, P.V., (2006) "Returns to Education: New Evidence for India", *Education Economics*, 14(4), pp431-451.

Jain, S.,(2004) "Education in India: A Crumbling Citadel", *Margin* 36(2), pp1-10.

Jeffrey,C., Jeffrey,R., and Jeffrey,P., (2004) " Degrees Without Freedom: The impact of formal education on Dalit young men in North India", *Development and Change*, 35(5), pp 963-986.

Kingdon,G.G., and Unni,J., (2001) "Education and Women's Labour Market Outcomes in India" *Education Economics*, 9(2), pp. 173-195.

Lewis,W.A., (1962) "Education and Economic Development", *International Social Science Journal*, 14(4), pp. 685-699.

Lucas,R., (1988) “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22(1), pp. 3-42.

Nagaraj, R., Varoudakis,A., and Veganzones,M., (2000) “ Long-run growth trends and convergence across Indian States”, *Journal of International Development*,12(1), pp 45-70.

Schultz,T.W., (1962) “ Reflections on Investment in Man”, *Journal of Political Economy*, 70, pp. S2-S3.